



ग्रामीण मज़दूरी में असमानताएँ

प्रलम्बिस् के लयिः

[भारतीय रज़िस्व बैंक](#), [ग्रामीण मज़दूरी](#), [मनरेगा](#), [महात्मा गांधी राषट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियम](#), [आतमनरिभर भारत रोज़गार योजना](#), [राषट्रीय कॅरयिर सेवा परयोजना](#), [दीनदयाल अंतयोदय योजना- राषट्रीय ग्रामीण आजीवकिा मशिन](#) ।

मेन्स के लयिः

भारत में वेतन असमानता के लयि ज़मिमेदार प्रमुख कारक, नीतयिों के डज़ाइन और कारयानवयन से उत्पन्न होने वाले मुददे ।

[स्रोतः इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

[भारतीय रज़िस्व बैंक](#) के हालयि आँकडे भारत के वभिन्न राज्यों में ग्रामीण मज़दूरी में भारी अंतर को उजागर करते हैं, जो कृषि और गैर-कृषि श्रमकिों की कमाई में गंभीर असमानताओं को दरशाता है ।

- वभिन्न राज्यों में ग्रामीण मज़दूरी में भारी अंतर समान वतियरण और नीतयिों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो इस असमानता को पाट सकते हैं, इससे देश भर में कृषि तथा गैर-कृषि श्रमकिों के लयि अधिक संतुलित आजीवकिा सुनश्चिति होगी ।

RBI के ग्रामीण मज़दूरी डेटा की प्रमुख वशिषताएँ क्य़ा हैं?

- ग्रामीण आर्थकि वयवधानः वतियीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रामीण अर्थवयवस्था को रोज़गार और आय के स्तर को प्रभावित करने वाली कोवडि-19 महामारी के कारण चुनौतयिों का सामना करना पड़ा ।
 - इसके बाद वतियीय वर्ष 2022-23 में बढी हुई मुदरासफीत दरों और बय़ाज दरों ने ग्रामीण मांग को काफी हद तक बाधित कर दयिा ।
 - इन कारकों ने देश भर के ग्रामीण कषेत्रों में रोज़गार के अवसरों और आय स्थरिता पर भारी प्रभाव डाला ।
- ग्रामीण मज़दूरी असमानताएँः मध्य प्रदेश में कृषि और गैर-कृषि श्रमकिों के लयि ग्रामीण मज़दूरी क्रमशः राषट्रीय औसत 229.2 रुपए और 246.3 रुपए से काफी कम है, जसिसे ग्रामीण परवारों की आजीवकिा प्रभावित हो रही है ।
 - केरल में वभिन्न कषेत्रों की तुलना में सबसे अधिक मज़दूरी दी जाती है, जहाँ ग्रामीण कृषि श्रमकि प्रतदिनि 764.3 रुपए कमाते हैं ।
 - ग्रामीण नरिमाण श्रमकिों की मज़दूरी के मामले में भी केरल और मध्य प्रदेश क्रमशः 852.5 रुपए और 278.7 रुपए दैनकि के साथ इस स्पेक्ट्रम के वपिरित छोर पर खडे हैं ।
- राषट्रीय औसत वेतनः
 - कृषि श्रमकिः 345.7 रुपए
 - गैर-कृषि श्रमकिः 348 रुपए
 - नरिमाण श्रमकिः 393.3 रुपए
- स्थरि ग्रामीण आय वृद्धिः वर्ष 2022-23 में वेतन वृद्धि के बावजूद ग्रामीण आय की संभावनाएँ कम रहीं, जसिसे वास्तवकि ग्रामीण वेतन वृद्धि रुक गई, इससे अर्थवयवस्था के असंगठित कषेत्र में अपूरण सुधार का संकेत मलित़ा है ।
 - उदाहरण के लयि मनरेगा में रोज़गार की मांग कम हो गई, लेकिन वर्ष 2022-23 में महामारी-पूर्व के स्तर से अधिक रही, जो वशिष रूप से असंगठित कषेत्र में अपूरण सुधार का संकेत है ।

भारत में मज़दूरी असमानता के लयि ज़मिमेदार प्रमुख कारक क्य़ा हैं?

- आर्थकि वकिास असमानताएँः आर्थकि वकिास के वभिन्न स्तरों वाले कषेत्र या राज्य पर्याप्त आय अंतर दरशाते हैं ।
 - उन्नत औदयोगिक कषेत्र कृषि-केंदरित कषेत्रों की तुलना में अधिक मज़दूरी वाला गैर-कृषि रोज़गार प्रदान करते हैं ।
- नीतगत हस्तकषेपः न्यूनतम मज़दूरी, श्रम नयिमों और सामाजकि सुरकषा योजनाओं के संबंध में वविधि राज्य-स्तरिय नीतयिों भी मज़दूरी में

असमानताएँ पैदा करती हैं। कड़े श्रम कानूनों वाले राज्य अधिक आय की पेशकश कर सकते हैं लेकिन रोज़गार के कम अवसरों का भी सामना करना पड़ सकता है।

- **बाज़ार और मांग-आपूर्ति की गतिशीलता:** मज़दूरी दरें अक्सर **वशिष्ट कौशल या श्रम** के लिये बाज़ार की मांग के अनुरूप होती हैं। कुछ क्षेत्रों में उच्च मांग और सीमित कार्यबल आपूर्ति वाले क्षेत्र उच्च मज़दूरी की पेशकश करते हैं।
- **जीवन यापन की लागत और जीवन स्तर:** जीवन यापन की लागत, **आवास व्यय और अन्य आवश्यक सुविधाओं** में भिन्नता सीधे मज़दूरी में असमानताओं को प्रभावित करती है। उच्च जीवन स्तर या आवश्यकताओं की उच्च लागत वाले क्षेत्र अक्सर कृषिपूरति के लिये उच्च मज़दूरी की पेशकश करते हैं।
- **भौगोलिक कारक और कृषि चक्र:** **मौसम की स्थिति** और **कृषि चक्र** ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। मौसमी उतार-चढ़ाव तथा कृषि गतिविधियों पर निर्भरता से **मौसमी मज़दूरी में बदलाव** आ सकता है।
- **प्रवासन और श्रम गतिशीलता:** **कम मज़दूरी वाले क्षेत्रों से उच्च भुगतान वाले क्षेत्रों की ओर श्रम की गतिशीलता** मज़दूरी में असंतुलन उत्पन्न करती है, जिससे स्रोत और गंतव्य दोनों क्षेत्रों की मज़दूरी संरचनाएँ प्रभावित होती हैं।

भारत सरकार की संबंधित पहलें क्या हैं?

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)**
- **आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY)**
- **नेशनल कॅरियर सर्विस (NCS) परियोजना**
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन (DAY-NRLM)**
 - **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)**
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)**

आगे की राह

- **कृषि विविधीकरण:** **पशुपालन, मत्स्यपालन और कृषि-प्रसंस्करण** जैसे संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
 - इससे पूरक आय स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं, कृषि पर निर्भरता कम हो सकती है और **समग्र आय में सुधार हो सकता है**।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना और नवाचार:** उत्पादकता बढ़ाने के लिये कृषि पद्धतियों में तकनीक को एकीकृत करना। **आधुनिक कृषि तकनीकों, मशीनरी और बाज़ार संपर्क तक पहुँच से ग्रामीण आय बढ़ सकती है**।
- **आधारभूत अवसंरचनात्मक विकास:** बेहतर सड़कों, **सिंचाई प्रणालियों तथा कनेक्टिविटी** सहित ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में निवेश करना।
 - बेहतर बुनियादी ढाँचा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकता है, रोज़गार के अवसर सृजित कर सकता है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में **उद्योगों को आकर्षित कर सकता है, जिससे मज़दूरी बढ़ने की संभावना है**।
- **प्रवासी श्रमिकों का कल्याण:** प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों तथा आजीविका की सुरक्षा के लिये नीतियों को लागू करना। इस कार्यबल के लिये **उचित वेतन, पर्याप्त रहने की स्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना** राज्यों में श्रम के संतुलित वितरण को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना:** इच्छुक कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहन, परामर्श तथा बाज़ार पहुँच प्रदान करके ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित एवं समर्थन करना।
 - इसका **व्यापक प्रभाव** हो सकता है, **नौकरियाँ सृजित हो सकती हैं तथा ग्रामीण आय में वृद्धि हो सकती है**।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

- (A) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (C) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (D) किसी भी घर के वयस्क सदस्य

उत्तर: (D)

व्याख्या:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (मनरेगा), जो दुनिया में सबसे बड़ा रोज़गार गारंटी कार्यक्रम है, को वर्ष 2005 में अधिनियमि किये गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य प्रतिवर्ष 100 दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देना था, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य

करने के लिये सवेच्छा से काम करते हैं।

- इसका उद्देश्य किये गए 'कार्यों' (परियोजनाओं) के माध्यम से गरीबी के कारणों को संबोधित करना है, और इस प्रकार सतत विकास सुनिश्चित करना है। पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को इन कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका देकर वकिंदरीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

अतः विकल्प D सही उत्तर है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rural-wage-disparities>

